ने कहा कि जो सरकार में मंत्री होता है वह सरकार पर सवार होता है। मैं जानता हूं कि मैं अपनी सरकार में ठीक-ठाक हैसियत रखता हूं, लेकिन सी.एम. इब्राहीम साहब के जमाने वाली हैसियत नहीं रखता हूं कि सारे जवाब इनको अभी दे सकता। ...(**व्यवधान**)...

श्री सी. एम. इब्राहीमः आपकी भी वही ताकत है। आपको वाजपेयी जी भी चाहते हैं और आडवाणी जी भी चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः सर, जैसा कि सम्मानित सदस्या ने पूछा है यह सवाल मेरे से रिलेटिड नहीं है। पूरे देश के मामलों से संबंधित सवाल मेरे से पूछा जा रहा है।

लघु उद्योगों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने का प्रभाव

*243. **श्रीमती सरोज दुबेः** क्या वस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार द्वारा वर्तमान वस्त्र नीति के तहत मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने से धरेलू व लघु कपड़ा उद्योगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कपड़ा उद्योगों को राहत व संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है। औऱ

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (**श्री काशी राम राणा**): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने के बाद वस्त्रों के आयात ने वृद्धि दर्शायी है। तथापि, कुल आयात, देश में वस्त्रों के वार्षिक घरेलू उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं है। इस प्रकार इनके आयात से घरेलू और लघु उद्योग पर कोई विषेश प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(ख) और (ग) सरकार आयात पर निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आयात से घरेलू उद्योग को किसी प्रकार का गंभीर नुकसान न हो अथवा प्रघात न पड़े। यदि किसी प्रकार के अनुचित व्यापार की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है, तो आवश्यकता पड़ने पर डब्ल्य टी ओ करार के अंतर्गत पाटन रोधी, प्रतिकारी और सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं।

Effect of withdrawal of Quantitative Restrictions on Small Scale Industries

†*243. SHRIMATI SAROJ DUBEY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the withdrawal of quantitative restrictions under the present textile policy by Government has badly affected domestic and small scale textile industries;

(b) if so, whether Government propose to take steps for providing relief and protection to such textile industries; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) After the withdrawal of quantitative restrictions, the imports of textile have shown an increase. However, the total imports are not even one per-cent of the annual domestic production of textiles in the country. The imports, thus, are not having any significant adverse impact on domestic and small scale industry.

(b) and (c) Government is keeping a watch on the imports and would strive to ensure that imports do not cause any serious detriment or injury to the domestic industry. In case any unfair trade practice comes to notice, action, if necessary, under anti-dumping, countervailing and safeguard measures under the WTO agreement, could be taken.

श्रीमती सरोज दुबेः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है कि सप्लीमेंटरी पूछने की सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका एक प्रतिशत भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री

†Original notice of the Question was received in Hindi.

जी से यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले जो घरेलू उद्योग हैं, उस क्षेत्र में उदारीकरण के पदार्पण के कारण उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जहां वैश्वीकरण और उदारीकरण को जरुरी माना जा रहा है, तो वहीं पर लघु और कुटीर उद्योगों को बचाना भी आपका कर्तव्य हो जाता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश में बस्त्र निर्माण और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का जो निर्यात होता है, उत्पादन होता है वह छोटी-छोटी कम्पनियों के द्वारा किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्णाटक के समाम प्रदेशों में हैंडलूम और पॉवरलूम के रुप में ये छोटे-छोटे उद्योग बिखरे पड़े हुए हैं। यह वस्त्र उद्योग हमारी कला और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और यह हमारे देश की एक अलग से पहचान भी बनाता है। इस वस्त्र उद्योग से पचास लाख से भी अधिक लोग अपना परिवार पालते हैं। लघु उद्योग अऔर उत्पादक मशीन से सिलकर सालाना करीब 32000 हजार करोड़ रुपये के रेडीमेड गारमेंट्स विदेशों को निर्यात करते हैं। आपने डब्ल्यू.टी.ओ. के "मल्टी फाइबर ऐग्रीमेंट" के तहत, देश में वस्त्र उद्योग में उदारीकरण को विशेष स्थान दे दिया है। एक तरफ तो आपने 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा दिया है और दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने निर्यात में ड्यूटी ड्राबैक में कमी कर दी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप इन उद्योगों को वित्त मंत्रालय की तुगलकी नीति से नहीं बचा पाए और इन उद्योगों को आपने गलाकाट प्रतियोगिता में धकेल दिया है। इसके कारण हमारे देश के करीब-करीब 40 हजार हैंडलूम बंद हो चुके हैं और आप कहते हैं कि इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। इन हैंडलूम्स के कर्मचारी और मज़दूर तो भूखे मर ही रहे हैं, साथ-साथ इनके मालिकों की हालत भी बहुत दयनीय हो रही है और वे भुखमरी के कगार पर पहंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारी विज्ञापनों के साथ आ रहीं हैं और इनको बाजार नियंत्रण के आक्रमक तरीके भी मालूम हैं। इसके अलावा इनको सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है इसलिए ये बड़ी भारी संख्या में आपके बाजार में उतरने वाली हैं क्योंकि आपका वस्त्र उद्योग आपकी गलत नीतियों के कारण बहुत मुश्किलों में पड़ गया है। मैं जानना चाहती हूं कि वस्त्र उद्योग को आप मल्टी नैशनल के वस्त्रों से जिनकी आपके यहां डम्पिंग होने वाली है, उससे और आपकी गलत नीतियों से कैसे बचाएंगे और साथ ही साथ जो घरेलू कुटीर उद्योग है, जो करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है, उसे बचाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे है? आपने उत्तर में लिखा है कि "इसके आयात से घरेलू और लघु उद्योगों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप कृपया यह बताएं कि अभी तक कितना आयात हुआ है और इस आयात से हमारी आयात और निर्यात की व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है?

श्री काशी राम राणाः सभापति महोदय, जो जवाब मैंने दिया है, वह बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस उठाने से- जैसा माननीय सदस्या ने कहा- हमारे देश में डम्पिंग होने की बहुत संभावना है। वैसे ही सरकार की ओर से और वस्त्र मंत्रालय की ओर से

भी भारत में अगर बाहर से टैक्सटाइल या गारमेंट की कोई भी आइटम यहां आती है तो इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जहां तक सवाल के जवाब का संबंध है, जो रेडिमेड गारमेंट 2000-2001 में इम्पोर्ट हुआ है वह 21.3 मिलियन यूएस डालर है। जबकि हमारा रेडिमेड गारमेंट में एक्सपोर्ट हुआ 5569.6 मिलियन डालर। इसीलिए हमने कहा कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शनन्स उठाने के बाद भी हमारा इम्पोर्ट बहुत ही कम है, जो निर्यात का करीब-करीब एक परसेंट है। इसके साथ ही मैं लेटेस्ट फिगर्स भी देना चाहता हूं। इम्पोर्ट पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन्स सरकार ने उठा लिया है, ऐसा नहीं है, यह सिलसिला चलता आ रहा है, अप्रैल 96 से। हमने जो 'गैट' एग्रिमेंट में रेस्ट्रेक्शन्स उठाना था भारत सरकार ने उस सर्किल को पूरा किया है। जो लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी है, उसमें बाकी 715 टैरिफ लाइन्स हटा दी गई है। इसमें 342 टेक्सटाइल की टैरिफ लाइन्स थीं। इसके बावजूद भी जो इस साल 2000-2001 में अप्रैल, मई का जो टोटल इम्पोर्ट हुआ है, उसके हिसाब से लास्ट ईयर अप्रैल-मई 2000 में 220.5 और अप्रैल-मई 2001 में 261.6 मिलियन डालर हुआ। इसीलिए यहां ज्यादा इम्पोर्ट नहीं हुआ और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। हमने जब यहां बजट पेश किया तो वित्त मंत्री जी ने एक टैक्सटाइल पैकेज पेश किया। हमारी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ठीक करने के लिए और इनटरनेशनल मार्किट में अच्छी तरह कम्पीट कर सकें, मुकाबला कर सकें इसके लिए अच्छी मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी 15 से 5 परसेंट कर दी। टैक्सटाइल पैकेज में अक्सेलरेटिड डेप्रिसियेशन 25 से 50 परसेंट का दिया है ताकि निर्यात करने वाले लोग अच्छी क्वालिटी बना सकें। सर, इतना ही नहीं हमने टैक्रोलोजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम शुरु की है, जो अच्छी जल रही है। हमने टैक्सटाइल पॉलिसी 2000 भी बनाई है और इसके तहत हम इस देश में 8 हजार शटललैस लूम्स को बढ़ाकर 50 हजार शटललैस लूम करने जा रहे हैं और जो सैमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक लूम्स हैं, उनमें ढाई लाख लूम बनाने के लिए हमने टैक्सटाइल पैकेज के तहत बजट में प्रावधान किया है। इतना ही नहीं हमने इस देश में अपेरल पार्क्स की योजना भी बनाई है क्योंकि हमारे सामने निर्यात में सबसे आगे देश चाइना, इन्डोनेशिया, थाईलैंड और मैक्सिको नाफटा कंट्री हैं, वहां पर रेडिमेड गारमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। उसी तरह की फैस्ट्रीज हमारे देश में भी लगें, इसलिए हमने अपेरल पार्क्स की योजना भी बनी है। ...(**व्यवधान**) माननीय सांसद को मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन्स उठाने के बाद हमारे जो घरेलू ...(**व्यवधान**) छोटे-छोटे उद्योग हैं, इनके लिए सरकार चिंतित है और कदम उठा रही है। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सरोज दुबेः सर, मंत्री जी का जवाब मेरे प्रश्न से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ...(**व्यवधान**) माननीय मंत्री जी, आपने यह नहीं बताया कि आपके निर्यात में कितनी कमी

आई है? इसके आलावा में आपसे जानना चाहती हूं कि इन लघु वस्त्र उद्योग के लिए सूत, जो उसका बुनियादी आधार होता है, जिस पर सारा उद्योग चलता है, इस सूत को रियायती दाम पर उपलब्ध कराने के लिए क्या आप कोई योजना बना रहे है? किस तरह से इन लोगों को प्रोत्साहन देंगे और इन्हें मल्टी नेशनल कंपनियों के चंगुल से कैसे बचाएंगे ताकि वस्त उद्योग जीवित रह सके? विदेशी निवेश को आप और कहां तक बढ़ाएंगे और आपने इन्हें अवसर क्यों दिया?

श्री काशी राम राणाः सभापति जी, माननीय सांसद ने तीन सवाल पूछ लिए। जहां तक निर्यात का सवाल है तो हमारा निर्यात 2001 में 12,097.6 मिलियन डालर हुआ है। इससे पहले साल में 10,508.6 मिलियन डालर का निर्यात हुआ था। मैं यह स्वीकार करुंगा कि जो पिछला क्वार्टर है, यानी कि पिछले दो महीनों में ...(**व्यवधान**)... मैं सदन के सामने सही बात बताऊंगा। ऐसा नहीं है ...(**व्यवधान**)... उसमें थोड़ी-बहुत गिरावट आई है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरीः उसका क्या कारण है...(**व्यवधान**)...

श्री काशी राम राणाः आप सुनेंगे तब न ...(**व्यवधान**)... आप सुनेंगे तब न ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए सरोज जी, आप सुनिए...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेशवरीः आपका विभाग क्या कर रहा था...(**व्यवधान**)...

श्री काशी राम राणाः सभापति जी, मैं फिगर दे रहा हूं कि अप्रैल में ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्रः महिलाएं बोल रही है ...(**व्यवधान**)...

श्री काशी राम राणाः सभापति महोदय, अप्रैल 2000 में 2128.2 मिलियन डॉलर का जो निर्यात हुआ था उसमें थोड़ी गिरावट आई है इस अप्रैल –मई में ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूं, आप जानती हैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबेः सर, इन्होंने सदन को मिसलीड किया है।

श्री काशी राम राणाः सभापति महोदय, जो 1,619.4 मिलियन डालर का निर्यात हुआ है और उसमें जो गिरावट आई है वह गिरावट हम जो सैकिण्ड क्वार्टर है उसमें रिट्रीव करेंगे। सभापति जी, इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि सूत ...(**व्यवधान**)...

श्रीमति सरला माहेश्वरीः हमारा सीधा सा सवाल है कि आपका विभाग क्या कर रहा था...(**व्यवधान**)... आपका विभाग चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा था...(**व्यवधान**)...

श्री काशी राम राणाः सभापति जी, इन्होंने तीसरा सवाल पूछा है कि सस्ते दाम पर सूत

कैसे उपलब्ध कराते हैं, तो जहां-जहां जरुरत होती है वहां-वहां यार्न का डिपो खोला है। हमारे हथकरघा क्षेत्र के जो वीवर हैं उन्हें सही दाम पर, सस्ते दाम पर सूत अवेलेबल कराने के लिए हर राज्य में यार्न बैंक खोलने के लिए पॉलिसी बनाई है। हमने कई राज्यों में यार्न बैंक खोले हैं और उसी के जरिये हम उपलब्ध कराते हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The Minister gave us the break-up. For the last five years, exports have continuously been going down. I am not talking about textile exports only, but exports as a whole. Is the hon. Minister aware—I have personal experiences, and I had written a letter to the hon. Minister—also—a large number of garment manufacturers, living in Calcutta, especially in Kidderpore, Garden Reach and Howrah, have lost their market because of the imported garments. It may be 1715 items. It may be one per cent of the overall import. But it is not a question of average import. It is a question of a particular item, which had earlier been restricted. No it has been allowed because of the qualitative restrictions. Will the hon. Minister look into the micro problems, instead of projecting an overall global problem?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the Government will definitely look into it because the Government is also interested in increasing the exports. So far as some units of West Bengal are concerned, because of the State Government's policy, the units...*(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, Leader of the House should intervene. This is not fair...*(Interruptions).* This kind of a reply is not fair...*(Interruptions).* The Leader of the House should calrify this...*(Interruptions).* You have used the House to denigrate the State Government. Is this the purpose of this House?...*(Interruptions).* It is very unfortunate.*(Interruptions)*

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI J AS WANT SINGH): Mr. Chairman, Sir. I understand the agitation among the hon. Members from West Bengal. I am sure, the State Government of West Bengal is not only fully seized of the seriousness of the issue, but no doubt, it is also doing everything possible.

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour is over.